बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 215 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 12 जून 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

डीएनडी से अक्षम जाने वालों के लिए जरूरी खबर, एक हफ्ते तक जाम से बढ़ेगी परेशानी; ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

नई दिल्ली। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दक्षिणी दिल्ली के लिए लोगों के लिए एक एजडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने बताया कि रिंग रोड के महारानी बाग से अक्षम वाले हिस्से पर दिल्ली जल बोर्ड का मरम्मत कार्य चल रहा है। इस काम की वजह से 11 जून से लगभग एक हफ्ते तक ट्रैफिक पर असर पड़ेगा। जल बोर्ड का सड़क के दो लेन पर काम चल रहा है, जिस कारण 24 घंटे गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित रहेगी। डीएनडी फ्लाईओवर से अक्षम की तरफ जाने वाली रिंग रोड और सी.वी. रमन मार्ग से रिंग रोड पर आने वाली गाड़ियां प्रभावित हो सकती है। पीक आवर्स में जाम की स्थिति बन सकती है। इसलिए पुलिस ने लोगों से अनुरोध किया है कि जरूरी हो तभी इस रास्ते से निकलें।

मानसून देगा झटका- दिल्ली-यूपी-बिहार और राजस्थान में कम होगी बारिश, फसलों पर सीधा असर

नई दिल्ली। भारत में मानसून की रफ्तार धीमी चल रही है। मौसम विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि अगले दो हफ्तों में भारत में, खासकर मध्य और उत्तरी इलाकों में, औसत से कम बारिश होने की उम्मीद है। मानसून के धीमा गति से चलने का कारण है पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस।

जून से सितंबर तक चलने वाला मानसून आमतौर पर 1 जून के आसपास दक्षिणी राज्य केरल में दस्तक देता है और जुलाई के मध्य तक पूरे देश में फैल जाता है, लेकिन इस साल केरल में मानसून के आने में तीन दिन की देरी हुई।

क्यों धीमा चल रहा मानसून?

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने सालाना मानसून की रफ्तार धीमी कर दी है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भूमध्य सागर से आने वाली मौसमी घटनाएं हैं जो उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी लाती हैं और कभी-कभी मानसून के बढ़ने में बाधा डालती हैं। देश की सालाना बारिश का लगभग 70फीसदी हिस्सा

मानसून से ही मिलता है और यह अहम जल स्रोतों को फिर से भरता है। भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग आधी खेती वाली जमीन पर सिंचाई की सुविधा नहीं है और लगभग आधी आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। जून से सितंबर तक चलने वाला मानसून आमतौर पर 1 जून के आसपास दक्षिणी राज्य केरल में दस्तक देता है और जुलाई के मध्य तक पूरे देश में फैल जाता है, लेकिन इस साल केरल में इसके आने में तीन दिन की देरी हुई। जून के पहले 10 दिनों में भारत में सामान्य से 26.5फीसदी कम बारिश हुई। मौसम विभाग ने पिछले महीने अनुमान लगाया था कि चार महीने के मॉनसून सीजन के दौरान भारत में लॉन्ग-पीरियड एवरेज का 90फीसदी बारिश होने की संभावना है, जबकि अल नीनो के असर से जून में एमपी का 92फीसदी बारिश होने की उम्मीद है।

धीमे मानसून से फसलों पर असर

मध्य और उत्तरी राज्यों में कम बारिश से चावल, कपास, सोयाबीन और दालों जैसी गर्मियों की फसलों की बुवाई में देरी हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने मॉनसून की रफ्तार धीमी कर दी है और इसे मध्य भारत में पहुंचने में कुछ और दिन लग सकते हैं। अधिकारी ने बताया कि मानसून अब तक केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों के साथ-साथ कर्नाटक और दक्षिणी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पहुंच चुका है, जहां अगले दो हफ्तों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। हालांकि, अधिकारी ने कहा कि मध्य और उत्तरी इलाकों में इस दौरान सामान्य से काफी कम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि जून के आखिरी हफ्ते में मानसून के जोर पकड़ने की उम्मीद है। इस समय ज्यादातर राज्यों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। दोनों अधिकारियों ने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें मीडिया से बात करने की इजाजत नहीं थी।

अंकित शर्मा हत्याकांड - 7 जुलाई को आएगा कड़कड़डूमा कोर्ट का फैसला, पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 11 आरोपी

पूर्वी दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हुए आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड मामले में अदालत सात जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी। गुरुवार को मामले में सुनवाई के दौरान निर्णय सुरक्षित रखते हुए न्यायालय ने फैसले के लिए सात जुलाई की तारीख निर्धारित की। इस बहुचर्चित मामले में पीड़ित पक्ष और आरोपितों सहित सभी की नजरें अब अदालत के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं। वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हुए सबसे चर्चित मामलों में से एक अंकित शर्मा हत्याकांड ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) में सुरक्षा सहायक के रूप में तैनात अंकित शर्मा 25 फरवरी 2020 की शाम अपने घर के पास से लापता हो गए थे। अगले दिन 26 फरवरी को चांदबाग क्षेत्र में स्थित एक नाले से उनका शव बरामद किया गया। उस समय दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा, आगजनी और पथराव की घटनाएं लगातार हो रही थीं। इस घटना ने दंगों की भयावहता को और उजागर कर दिया और सुर्खियों में छा गया।दयालपुर थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर पुलिस ने गहन जांच की। जांच के दौरान पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत कुल 11 आरोपितों के खिलाफ हत्या, दंगा, आपराधिक साजिश तथा अन्य गंभीर धाराओं के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया।

अंकित शर्मा को निशाना बनाकर उनकी हत्या की गई

अभियोजन पक्ष का दावा है कि दंगों के दौरान अंकित शर्मा को निशाना बनाकर उनकी हत्या की गई और बाद में शव को नाले में फेंक दिया गया। वहीं बचाव पक्ष ने सभी आरोपों से इनकार किया है और मामले को झूठा बताया है। दोनों पक्षों ने अदालत में अपनी-अपनी दलीलें पूरी कर दी हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत में इस मामले का फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। अब सभी की निगाहें अदालत के अंतिम निर्णय पर टिकी हुई हैं। यह मामला दिल्ली दंगों से जुड़े प्रमुख मुकदमों में शामिल है, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी स्तर पर काफी बहस हुई है।

विदेश से मिल रहे थे आदेश, दिल्ली पुलिस ने टिल्लू गैंग का खूनी प्लान किया फेल, 2 शूटर गिरफ्तार

नई दिल्ली।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए टिल्लू ताजपुरिया गैंग के दो शार्पशूटरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि दोनों आरोपी अपने प्रतिद्वंद्वी गोगी गैंग के प्रमुख सदस्यों की हत्या की साजिश रच रहे थे. उनकी गिरफ्तारी से दिल्ली-एनसीआर में होने वाली दो संभावित हत्याओं को टाल दिया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 24 वर्षीय जतीन और 33 वर्षीय विनय मान उर्फ बिट्टू के रूप में हुई है. पुलिस ने इनके कब्जे से दो हथियार, सात जिंदा कारतूस और विदेश में बैठे गैंग सरगनाओं से संपर्क के लिए इस्तेमाल किया जा रहा मोबाइल फोन बरामद किया है. पुलिस के मुताबिक टिल्लू ताजपुरिया और गोगी गैंग के बीच साल 2014 से खूनी दुश्मनी चली आ रही है. दोनों गैंगों के सरगनाओं की मौत के बाद भी उनके गुर्गे एक-दूसरे को निशाना बनाते रहे हैं. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि विदेश में छिपे टिल्लू गैंग के सदस्य अपने साथियों के जरिए गोगी गैंग के लोगों की हत्या करवाने की योजना बना रहे हैं. इसके बाद पुलिस ने करीब एक महीने तक निगरानी और जांच की..जांच के दौरान पता चला कि गैंग के कुछ सदस्य अपने टारगेट की रेकी कर रहे हैं. 8 जून को पुलिस ने जतिन को उस समय गिरफ्तार किया जब वह कथित तौर पर गोगी गैंग के एक सदस्य को निशाना बनाने जा रहा था. उसके पास से एक पिस्टल और पांच कारतूस बरामद हुए. दिल्ली पुलिस की पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वह पिछले एक महीने से अपने साथियों के साथ मिलकर टारगेट की जानकारी जुटा रहा था..जतिन से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने हरिद्वार से विनय मान उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार किया. उसकी निशानदेही पर एक रिवॉल्वर और दो कारतूस बरामद किए गए. दिल्ली पुलिस जांच में सामने आया कि वर्ष 2017 में बिट्टू के पिता की हत्या कर दी गई थी. बिट्टू को शक था कि इस वारदात के पीछे गोगी गैंग का हाथ था. पिता की मौत का बदला लेने के लिए उसने टिल्लू ताजपुरिया गैंग से संबंध बना लिए और गैंग के लिए काम करने लगा. पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी विदेश में बैठे गैंग हैंडलरों के संपर्क में थे और एन्क्रिप्टेड वॉयस ऐप्स के जरिए निर्देश ले रहे थे. पूछताछ में गैंग के काम करने के तरीके और उसके नेटवर्क से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली हैं. मामले की आगे जांच जारी है और पुलिस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है.

गृहिणियां राष्ट्रनिर्माता, इनके घरेलू काम की कीमत 30 हजार प्रतिमाह; किस केस में आया आदेश?

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सड़क हादसों में जान गंवाने वाली गृहिणियों के काम की कीमत कम से कम 30,000 रुपये महीना मानी जानी चाहिए। मुआवजे की गणना करते समय इस राशि को आधार करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा की कि गृहिणियों को राष्ट्र निर्माता के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। देश भर में मोटर दुर्घटना के मामलों में मुआवजा तय करने के तरीके को बदलने वाले इस अहम फैसले में, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने होममेकर्स की काल्पनिक आय को कुशल मजदूरों की मजदूरी के बराबर मानने की पुरानी न्यायिक प्रथा को खारिज कर दिया। जिसमें गृहिणियों की आय को कुशल मजदूरों की दिहाड़ी के बराबर माना जाता था। कोर्ट ने कहा कि घर के कामों की सामाजिक और आर्थिक अहमियत बहुत ज्यादा है। इसे केवल सामान्य मजदूरी के तराजू में नहीं तौला जा सकता। जस्टिस करोल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि घरेलू देखभाल के नुकसान की भरपाई के लिए 30,000 रुपये का नया नियम बनाया गया है। यह राशि %प्रणय सेठी केस में तय किए गए अन्य लाभों के अतिरिक्त होगी। यह मामला पंजाब की रेशमा नाम की महिला से जुड़ा है। उनकी मौत नवंबर 2001 में एक सड़क हादसे में हुई थी। उनके पति और तीन बच्चों ने मुआवजे के लिए ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था। ट्रिब्यूनल ने 2003 में फैसला दिया, लेकिन कानूनी लड़ाई वर्षों तक चलती रही। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पर दिसंबर 2024 में फैसला सुनाया। हादसे के 23 साल बाद आए इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मोटर एक्सीडेंट से जुड़े दावों का निपटारा आमतौर पर एक साल के भीतर हो जाना चाहिए। कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध किया कि वे ऐसे मामलों की निगरानी करें। उन्होंने उचित प्रशासनिक निर्देश जारी करने को कहा ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके। यह फैसला पूरे देश में मुआवजे के पुराने तरीकों को बदल देगा। अब तक अदालतें गृहिणियों की आय न्यूनतम मजदूरी के आधार पर तय करती थीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि घर के काम को सामान्य लेबर मार्केट के पैमानों से नहीं मापा जा सकता। इससे पहले भी कीर्ति बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस और अरुण कुमार अग्रवाल जैसे मामलों में कोर्ट ने कहा था कि गृहिणियों का योगदान अमूल्य है। नया फैसला मुआवजे की राशि को काफी बढ़ा देगा और पीड़ितों को आर्थिक मजबूती देगा।

उत्तर पूर्वी दिल्ली के गौतमपुरी में घर में मृत मिली महिला, पति पर शक; पुलिस जांच में जुटी

नई दिल्ली । उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर स्थित गौतमपुरी इलाके में एक दुखद घटना सामने आई है। 11 जून 2026 की सुबह 35 वर्षीय एक महिला अपने घर में मृत पाई गई। स्थानीय पुलिस को कथित हमले की सूचना मिली, जिसके बाद सीलमपुर पुलिस स्टेशन से तत्काल प्रतिक्रिया दी गई। पुलिस अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने वहां महिला का शव बरामद किया। शव को आगे की जांच के लिए जेपीसी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि महिला को सिर में गंभीर चोट लगी थी। यह चोट किसी भारी वस्तु से पहुंचाई गई होगी। इन चोटों के कारण ही उसकी मौत हुई। पुलिस रिपोर्टों के अनुसार, महिला का पति इस मामले में मुख्य संदिग्ध के रूप में सामने आया है। जांचकर्ताओं ने बताया कि घटना के तुरंत बाद आरोपी पति ने एक दोस्त से संपर्क किया था। उसने अपने दोस्त को बताया कि उसने अपनी पत्नी को थप्पड़ मारा था।

दिल्ली में गुरु रंधावा के जिम के बाहर फायरिंग, हमले के पीछे लॉरेंस गैंग

नई दिल्ली । पश्चिम विहार स्थित गायक गुरु रंधावा के जिम पर गोलीबारी की घटना सामने आई है। इस वारदात में किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया है और इसकी छानबीन शुरू कर दी है। इस गोलीबारी की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य ने ली है। अनिल पंडित नामक यह सदस्य अमेरिका में बैठा है। उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए यह दावा किया है। अनिल

पंडित ने अपनी पोस्ट में इस हमले का कारण बताया है। उसने दावा किया कि गुरु रंधावा अभिनेता सलमान खान के बहुत करीब हो रहे थे। गैंग ने पहले भी गुरु रंधावा को इस बारे में चेतावनी दी थी। अनिल पंडित के अनुसार, गुरु रंधावा ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज किया। इसी कारण से यह गोलीबारी की घटना हुई है। पुलिस टीम सभी पहलुओं से जांच कर रही है। पश्चिम विहार में यह महत्वपूर्ण घटना हुई है। यह घटना प्रसिद्ध गायक गुरु रंधावा के जिम से संबंधित है। उनके जिम परिसर पर अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की है। गोलीबारी की इस वारदात में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिलने से राहत की खबर है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य अनिल पंडित ने हमले की जिम्मेदारी ली है। उसने सोशल मीडिया पर अपने दावे को सार्वजनिक किया है। अनिल पंडित ने कहा कि गुरु रंधावा को सलमान खान से दूरी बनाने को कहा गया था। पुलिस इस मामले की विस्तृत छानबीन कर रही है। वे गोलीबारी करने वालों की पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही, अनिल पंडित के दावों की सत्यता की भी जांच की जा रही है।

दिल्ली की 72 लाख में से सिर्फ 10 हजार इमारतों में सुरक्षा सिस्टम, अब अनिवार्य बनाने की तैयारी

नई दिल्ली । दिल्ली में एक महीने के भीतर हुए दो भीषण अग्निकांडों ने आग से सुरक्षा के मौजूदा इंतजामों की पोल खोल दी है. 31 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद अब दिल्ली फायर सर्विस ने पूरे शहर की इमारतों के लिए नए सुरक्षा मानक लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है. विभाग ने दिल्ली सरकार को एक प्रस्ताव भेजकर सभी भवनों में स्मोक डिटेक्टर और स्प्रिंकलर सिस्टम अनिवार्य करने की सिफारिश की है. अधिकारियों का दावा है कि यदि यह व्यवस्था लागू हो जाती है तो आग से होने वाली मौतों में 97 प्रतिशत तक कमी लाई जा सकती है. फायर विभाग ने यह प्रस्ताव विवेक विहार में तीन मई को हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद सरकार को भेजा था. इस हादसे में एक रिहायशी इमारत में एसी ब्लास्ट के बाद आग भड़क गई थी, जिसमें दो परिवारों के नौ लोगों की जान चली गई थी. मृतकों में छोटे बच्चे भी शामिल थे. इसके ठीक एक महीने बाद, तीन जून को दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में लगी आग ने स्थिति की गंभीरता को और बढ़ा दिया. इस हादसे में 22 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 13 विदेशी नागरिक भी शामिल थे. इन दोनों घटनाओं ने राजधानी में अग्नि सुरक्षा उपायों को लेकर नई बहस छेड़ दी है. फायर अधिकारियों के अनुसार दोनों इमारतों में शुरुआती चेतावनी देने वाले उपकरण मौजूद नहीं थे. न तो स्मोक डिटेक्टर लगाए गए थे और न ही ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम उपलब्ध था. विभाग का मानना है कि यदि ये सिस्टम मौजूद होते तो लोगों को समय रहते आग की जानकारी मिल सकती थी और बचाव के लिए अधिक समय मिलता. प्रस्तावित व्यवस्था के तहत स्मोक डिटेक्टर धुआं फैलना शुरू होने के करीब 15 सेकंड के भीतर अलर्ट जारी कर देंगे.

इ

वहीं स्प्रिंकलर सिस्टम तापमान 68 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचते ही स्वतः सक्रिय होकर पानी का छिड़काव शुरू कर देगा. इससे आग को शुरुआती चरण में ही नियंत्रित करने की संभावना बढ़ जाएगी. दिल्ली फायर सर्विस के आंकड़ों के मुताबिक राजधानी में हर वर्ष औसतन लगभग 100 लोगों की मौत आग लगने की घटनाओं में होती है. विभाग का दावा है कि आधुनिक अग्नि सुरक्षा तकनीक के व्यापक इस्तेमाल से यह संख्या घटकर केवल तीन तक पहुंच सकती है. अधिकारियों का कहना है कि आग को फैलने से पहले रोकना ही सबसे प्रभावी बचाव रणनीति है. फायर विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक भवनों की बनावट ने आग की घटनाओं को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है. कम वेंटिलेशन, एयर कंडीशनर का बढ़ता उपयोग, सिंथेटिक फर्नीचर और अन्य कृत्रिम सामग्री आग को तेजी से फैलने में मदद करती है. यही वजह है कि एक दशक पहले किसी कमरे में आग के पूरी तरह फैलने में जहां 15 से 17 मिनट लगते थे, वहीं अब यह समय घटकर लगभग पांच मिनट रह गया है. ऐसे में शुरुआती कुछ सेकंड और मिनट ही लोगों की जान बचाने में निर्णायक साबित होते हैं. राजधानी में करीब 72 लाख इमारतें मौजूद हैं, जबकि स्मोक डिटेक्टर और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सुरक्षा प्रणाली केवल लगभग 10 हजार भवनों तक ही सीमित है.

सम्पादकीय...

साजिश..

जून 1984 की घटनाएं सिख इतिहास का एक अत्यंत पीड़ादायक अध्याय है। उस दौर में हुई त्रासदी ने हजारों परिवारों को प्रभावित किया और आज भी उससे जुड़ी भावनाएं सिख समाज के मन में जीवित हैं, लेकिन दुखद यह है कि कुछ खालिस्तान समर्थक संगठन आज भी उन घटनाओं का उपयोग युवाओं को भड़काने, समाज में नफरत फैलाने और अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। हाल ही में बब्बर खालसा इंटरनेशनल द्वारा जारी बयान ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि खालिस्तान समर्थक संगठनों का वास्तविक उद्देश्य सिखों के अधिकारों की रक्षा नहीं, बल्कि अलगाववाद और हिंसा की राजनीति को जीवित रखना है। इस बयान में न केवल भारत विरोधी प्रचार किया गया, बल्कि खुले तौर पर यह दावा भी किया गया कि खालिस्तान केवल हथियारबंद संघर्ष के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है। यह विचार न केवल लोकतंत्र और कानून के खिलाफ है, बल्कि सिख धर्म की मूल शिक्षाओं के भी विपरीत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बयान ने स्वयं खालिस्तान समर्थक खेमे के भीतर गहरे मतभेदों को उजागर कर दिया है। एक ओर कुछ संगठन चुनावी राजनीति, जनमत-संग्रह और राजनीतिक अभियान की बात करते हैं, जबकि दूसरी ओर ऐसे संगठन उन्हें भी अस्वीकार करते हुए हिंसक संघर्ष को ही एकमात्र रास्ता बताते हैं। यह दर्शाता है कि खालिस्तान आंदोलन कोई एकजुट विचारधारा नहीं, बल्कि परस्पर विरोधी गुटों का समूह है, जिनमें नेतृत्व और प्रभाव की होड़ लगी हुई है। विडंबना यह है कि जो संगठन स्वयं यह तय नहीं कर पा रहे कि उनका लक्ष्य कैसे हासिल होगा, वे सिख युवाओं को भविष्य का सपना दिखा रहे हैं। कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं, कोई आर्थिक योजना नहीं, कोई प्रशासनिक ढांचा नहीं और न ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई वास्तविक समर्थन। आज दुनियाभर में बसे सिख अपनी मेहनत, ईमानदारी और सेवा-भाव के कारण सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत सहित अनेक देशों में सिख समाज ने शिक्षा, व्यापार, सेना, राजनीति और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है, लेकिन जब कुछ चरमपंथी संगठन हिंसा और अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं तो उसकी कीमत पूरी सिख कौम को अपनी छवि के रूप में चुकानी पड़ती है। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि विदेशों में बैठे कुछ तत्व पंजाब के युवाओं को भावनात्मक नारों के माध्यम से प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि स्वयं वे सुरक्षित वातावरण में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि हिंसा का रास्ता केवल विनाश, खून-खराबे और सामाजिक अस्थिरता की ओर ले जाता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान आम सिख परिवारों को उठाना पड़ता है। सैकड़ों करोड़ का बजट, फिर भी फीस के अभाव में मर गई सिख बेटी - अमृतसर की 17 वर्षीय छात्रा अमजोत कौर की मौत केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि यह उन संस्थाओं के लिए भी एक कठोर प्रश्न है जो वर्षों से सिख समाज की सेवा के बड़े-बड़े दावे करती रही हैं। शिरोमणि कमेटी स्वयं को दुनिया की सबसे बड़ी सिख धार्मिक संस्था बताती है। हर वर्ष उसके पास करोड़ों रुपये की आय आती है। सेवा, शिक्षा और समाज कल्याण के नाम पर अनेक योजनाओं का प्रचार भी किया जाता है, लेकिन यदि वास्तविकता यह है कि किसी गरीब सिख परिवार की बेटी फीस के अभाव में मानसिक तनाव का शिकार होकर अपनी जान गंवा देती है तो यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यह विशाल बजट आखिर किसके लिए है? यह व्यवस्था पर सवाल है जिसके पास सैकड़ों करोड़ रुपये का बजट है, हजारों एकड़ संपत्ति है, करोड़ों श्रद्धालुओं का समर्थन है, लेकिन फिर भी जरूरतमंद सिख परिवारों तक समय पर सहायता नहीं पहुंच पाती। गुरुद्वारों में रोज लाखों लोगों को लंगर खिलाना निस्संदेह महान सेवा है, लेकिन सेवा केवल लंगर तक सीमित नहीं हो सकती। गुरु साहिबानों ने भूखे को भोजन देने के साथ-साथ जरूरतमंद की हर प्रकार से सहायता करने की शिक्षा दी है। यदि किसी बच्चे की पढ़ाई पैसे के अभाव में रुक रही हो, यदि कोई विधवा अपने बच्चों की फीस भरने में असमर्थ हो, यदि कोई गरीब परिवार शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहा हो तो सबसे पहले धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि आज संस्था का ध्यान वास्तविक समाज सेवा से अधिक राजनीति, चुनावों, गुटबाजी और सत्ता संघर्ष पर दिखाई देता है। मंचों से बड़े-बड़े भाषण दिए जाते हैं, करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट घोषित किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कितने जरूरतमंद परिवारों तक सहायता पहुंचती है, यह सवाल अक्सर अनुत्तरित रह जाता है। यदि अमजोत कौर जैसी बेटियां आर्थिक मजबूरी के कारण जीवन हार रही हैं तो यह केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे संस्थागत ढांचे की विफलता है।

गांधी के सपनों को साकार करते मोदी

वर्ष 2015 की बात है। अपने तत्कालीन सरकारी आवास, 10 अशोक रोड, नई दिल्ली पर मैंने एक बड़ा होर्डिंग लगवाया था। उस पर महात्मा गांधी और नरेंद्र मोदी की तस्वीरें थीं तथा शीर्षक था-साबरमती के दो संत। कुछ लोगों ने इसकी प्रशंसा की तो कुछ ने इसकी आलोचना। मीडिया के एक वर्ग ने यह कह कर प्रश्न उठाए कि क्या नरेंद्र मोदी की तुलना महात्मा गांधी से की जा सकती है। उस समय मैंने केवल इतना कहा था कि मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति की तुलना करना नहीं, बल्कि उन विचारों और मूल्यों की ओर ध्यान आकर्षित करना है जिन्हें महात्मा गांधी ने देश के सामने रखा था और जिन्हें नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन तथा शासन की नीतियों में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक पद पर लगातार 12 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, तब पीछे मुड़कर देखने पर मुझे लगता है कि उस होर्डिंग के पीछे जो भावना थी, वह समय के साथ और अधिक स्पष्ट हुई है। स्वभाव, परिस्थितियों और युग की भिन्नताओं के बावजूद एक तथ्य निर्विवाद रूप से सामने आता है कि प्रधानमंत्री मोदी का कार्य, उनका कृतित्व और उनकी अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं महात्मा गांधी के सपनों और आदर्शों को व्यवहार में उतारने का प्रयास करती हैं। कुछ लोग गांधीवादी इसलिए कहलाए, क्योंकि उन्होंने गांधी के सिद्धांतों को अपने निजी जीवन में अपनाया, जबकि नरेंद्र मोदी की विशेषता यह है कि उन्होंने गांधी के अनेक विचारों को शासन और जनजीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास किया। दूसरे शब्दों में कहें तो महात्मा गांधी को मन, वचन और कर्म से अपनाने तथा उनके विचारों को जन-आंदोलन का स्वरूप देने का जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, वह स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक उल्लेखनीय अध्याय है। गांधी कहा करते थे कि स्वच्छता स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के दशकों बाद भी स्वच्छता राष्ट्रीय प्राथमिकता नहीं बन सकी थी। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ कर इसे जन-आंदोलन का रूप दिया। देशभर में करोड़ों शौचालयों का निर्माण हुआ, खुले में शौच की समस्या में व्यापक कमी आई और स्वच्छता को लेकर सामाजिक चेतना विकसित हुई। यह केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि लोगों की सहभागिता वाला राष्ट्रीय अभियान बन गया। स्वच्छ भारत अभियान को महात्मा गांधी के स्वच्छ और स्वस्थ भारत के स्वप्न की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा सकता है। गांधी जी का स्वदेशी आंदोलन केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक सीमित नहीं था। उसका मूल उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना था। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिया गया आत्मनिर्भर भारत का मंत्र उसी विचार का आधुनिक विस्तार है। 'मेक इन इंडिया', 'वोकल फॉर लोकल', उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं, स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा-ये सभी प्रयास भारत को आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हैं। आज भारत मोबाइल निर्माण, डिजिटल भुगतान, रक्षा उत्पादन और अनेक औद्योगिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है।प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, ग्रामीण सड़क निर्माण, बिजली कनेक्शन, डिजिटल कनेक्टिविटी और ग्रामीण बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया। आज लाखों ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंच रहा है, गांव डिजिटल सेवाओं से जुड़ रहे हैं और आधारभूत सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यद्यपि गांधीजी के आदर्श ग्राम स्वराज की यात्रा अभी अधूरी है, लेकिन ग्रामीण विकास को राष्ट्रीय विकास के केंद्र में लाने का प्रयास निश्चित रूप से उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गांधी जी का प्रसिद्ध ताबीज हमें याद दिलाता है कि किसी भी निर्णय का मूल्यांकन उस अंतिम व्यक्ति के हित को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए जो सबसे अधिक कमजोर और वंचित है। प्रधानमंत्री मोदी की अनेक योजनाएं इसी विचार को आगे बढ़ाती दिखाई देती हैं। प्रधानमंत्री जन-धन योजना ने करोड़ों गरीबों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा। आयुष्मान भारत योजना ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चलाई गई योजनाओं का प्रभाव केवल नीतिगत घोषणाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसके ठोस परिणाम भी दिखाई दिए हैं। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत आज 58 करोड़ से अधिक नागरिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं और खातों में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाकर स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराया गया है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि गांधी जी के स्वच्छता, आत्मनिर्भरता, ग्रामोदय और अंत्योदय के विचार केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्हें व्यावहारिक रूप देने का प्रयास भी हुआ है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि उन विचारों को नए युग में आगे बढ़ाने का प्रयास भी हैं जिन्हें महात्मा गांधी ने स्वतंत्र भारत के लिए अपने सपनों में देखा था।

बर्थडे गिफ्ट

बच्चों के लिए मां प्रेम और स्नेह का प्रतीक होती है। वे निस्वार्थ प्रेम प्रदान करती है और तब तक उनका पालन-पोषण करती है जब तक कि वे आत्मनिर्भर न हो जाएं। दूसरी ओर, पिता अधिकांश बच्चों के लिए एक शक्ति होते हैं। उनके जीवन को पिता की उपस्थिति से मजबूती मिलती है। शायद आप इसे महसूस न करें, लेकिन पिता की उपस्थिति मात्र ही एक मार्गदर्शक की तरह होती है जो हर समय आपके आसपास रहता है। आज मेरे पिता पंजाब केसरी के पूर्व मुख्य सम्पादक और पूर्व सांसद श्री अश्विनी कुमार का जन्मदिवस है। मुझे याद है कि आपको जन्मदिन मनाने का बहुत शौक था। आपका जन्मदिन मेरे लिए और मेरे अनुजों अर्जुन, आकाश के लिए भी खुशी का सबब होता। पिताश्री जब हमारा जन्मदिन मनाते या मेरी मां किरण चोपड़ा के जन्मदिन पर पार्टी करते तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। दोस्तों के बीच रहना और खुलकर जीना उनकी आदत रही। दोस्तों के बीच उनकी दीवानगी देख सभी कहने लगते थे- आज भी हम उनका जन्मदिन उनके दोस्तों के बीच मनाएंगे। मैं समझता हूं शब्दों से भरा सागर भी आज हमारी भावनाओं को चित्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। भावुकता के क्षणों के बीच मैं महसूस करता हूं कि मेरे लिए मेरी मां दृढ़ता और संकल्प की प्रतीक हैं। उन्होंने हम सब के और परिवार के लिए हर सम्भव प्रयास किया। वहीं दूसरी ओर मेरे पिता प्रेरणा के स्रोत और धैर्य की साक्षात मूर्ति थे। मैंने उनसे मौन का महत्व सीखा। उनका मौन मेरे लिए उनके शब्दों से कहीं अधिक गहरा अर्थ रखता था। वे मेरे आदर्श थे और हमेशा रहेंगे। पत्रकारिता तो उन्हें विरासत में मिली थी। डीएवी कालेज जालंधर से ग्रेजुएशन और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर तक की शिक्षा प्राप्त की लेकिन उनकी दिलचस्पी क्रिकेट में थी। कई वर्षों तक वह रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी में फ्रंट फुट पर खेले। गेंदबाजी और बल्लेबाजी के क्षेत्र में उन्हें दक्षता प्राप्त थी। उनकी पहचान आल राउंडर के तौर पर स्थापित हो चुकी थी। उन्हें नेशनल टीम में खेलने का अवसर मिला लेकिन आपातकाल और फिर उसके बाद आतंकवाद ने उनके जीवन की धारा ही बदल दी। पूजनीय दादा श्री रमेश चन्द जी की शहादत के बाद उन्होंने कलम सम्भाली तो जीवन के अंतिम क्षण तक लिखते रहे। उन्हें अपने निर्भीक विचारों और स्वतंत्र लेखनी के लिए जाना जाता है। उनके सम्पादकीय लेख के लाखों लोग प्रशंसक रहे। मेरे पड़दादा और दादा की शहादत के बाद भी उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध लेखन नहीं छोड़ा। वह करनाल संसदीय सीट से भारी मतों से जीत कर सांसद भी बने लेकिन कलम छोड़ना उन्हें गवारा न था। जीवन चलता रहता है। हर बाधा एक अवसर लेकर आती है। अश्विनी जी स्वयं स्वामी विवेकानंद की पंक्तियों का स्मरण करते थे-दूसरे तुम्हारा क्या मूल्यांकन करते हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि तुम स्वयं को कितना महत्वपूर्ण मानते हो। मेरे पिता के व्यक्तित्व का आंकलन न तो भाई कर सकता है, न ही अन्य रिश्तेदार। कोई रिश्ता उनका आंकलन कर ही नहीं सकता है। मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने जो भी जीवन में किया बड़ी शिद्दत के साथ किया। सोचता हूं कि उनकी कलम में ऐसी कौन सी ताकत थी जो लाखों पाठकों को दीवाना बना देती थी। मुझे आज इस बात की खुशी है कि दिल्ली की श्रीमती रेखा गुप्ता सरकार ने मेरे पिता के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हुए ब्रिटेनिया चौक का नामकरण अश्विनी चोपड़ा मिन्ना के नाम पर करने का फैसला किया है। पंजाब केसरी परिवार उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। यह मेरे पिताजी को बहुत बड़ा हैप्पी बर्थडे गिफ्ट है।

इनके सपने मरने नहीं चाहिए

यह संतोष की बात है कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का दिल्ली में जंतर मंतर पर आयोजन शांतिमय ढंग से हो गया। सरकार ने समझदारी दिखाई और टकराव का रास्ता नहीं अपनाया। युवाओं को अपनी भड़ास निकालने का मौका दिया, जैसा लोकतंत्र में होना भी चाहिए। सीजेपी के नेताओं ने भी समझदारी दिखाई। अभिजीत दिपके ने बार-बार शांति की अपील की। सोनम वांगचुक का भी कहना था कि यह अपील है, प्रोटेस्ट नहीं। वह सरकार से टकर नहीं लेना चाहते इसीलिए शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग मनवाने के लिए एक सप्ताह का समय और दे दिया है। सरकार के लिए धर्म संकट है। अगर वह इस्तीफ़ा लेती है तो लगेगा कि सरकार झुक गई है जो प्रभाव यह सरकार नहीं देना चाहेगी। पर अगर वह इस्तीफ़ा नहीं देते तो प्रभाव यह जाएगा कि सरकार युवाओं की चिन्ता के प्रति संवेदनशील नहीं है। यह सम्भावना भी है कि आंदोलन देश भर में फैल जाए क्योंकि परीक्षा में हुए घपले से देशभर के युवा और उनके परिवार प्रभावित हैं। मोदी सरकार के लिए किसान आन्दोलन के बाद यह दूसरी बड़ी सामाजिक चुनौती है। बेहतर होगा कि धर्मेन्द्र प्रधान को किसी और विभाग में भेज दिया जाए क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में इतना बड़ा संकट पहले नहीं देखा गया। लोकतंत्र में अपने लोगों की मांग के आगे झुकना कमजोरी नहीं मानी जाती। इसे लोक भावना के प्रति संवेदनशीलता कहा जाता है। चीन से पराजय के बाद लोगों के दबाव में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को रक्षामंत्री कृष्णा मेनन को हटाना पड़ा था। बड़ा उदाहरण लाल बहादुर शास्त्री का है जिन्होंने दो रेल दुर्घटनाओं के बाद खुद इस्तीफ़ा दे दिया था। पहली बार नेहरू ने रोक दिया था, पर जब दूसरी बार रेल दुर्घटना हुई तो शास्त्री जी अड़ गए कि इस्तीफ़ा स्वीकार किया जाए। पर यहां तो बार-बार पेपर लीक हो रहे हैं, पर न धर्मेन्द्र प्रधान खुद इस्तीफ़ा दे रहे हैं, न उनसे लिया जा रहा है। सीबीएसई के दो अफ़सरों का तबादला कर दिया गया। पर क्या हज़ारों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए यह पर्याप्त सजा है? नीट-यूजी पेपर लीक और रद्द होने के अवसाद में मध्य प्रदेश की आकांक्षा ने आत्महत्या कर ली। मां-बाप के लिए छोड़े पत्र में वह लिख गई कि दोबारा तैयारी करने की हिम्मत नहीं है। नीट रद्द होने के बाद छह अभ्यर्थी आत्महत्या कर चुके हैं। अगर पेपर लीक न होता तो आकांक्षा और यह पांच बच्चे आज जीवित होते। इनकी मौत के लिए कौन जिम्मेवार है? कब ठोस जवाबदेही तय होगी कि आगे किसी आकांक्षा को अपनी जान न लेनी पड़े और मां-बाप बिलखते न रह जाएं? जन्तर मंतर पर जो कहा गया वह ही संदेश नहीं था, जैसी उपस्थिति थी वह खुद में बड़ा संदेश था। युवा तो थे ही। एक 11 वर्ष का बच्चा भी था जिसे अपने भविष्य की चिन्ता है। चिन्ता है कि वह रात-दिन जाग कर पढ़ाई करेगा, मां-बाप के पैसे खर्च करेगा, पर कोई और एग्ज़ाम को ही हाइजैक कर ले जाएगा। वहां एक बाप भी उपस्थित थे जो खुद को भाजपा समर्थित कह रहे थे, पर अब खफ़ा है, क्योंकि उनके बेटे की नीट-यूजी परीक्षा पेपर लीक होने के कारण दोबारा हो रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफ़ेसर नन्दिता नारायण का कहना था कि युवा जाग चुके हैं। अपनी बेटी के साथ वहां मौजूद शिल्पा का कहना था, जब बच्चे सालों परीक्षा की तैयारी करते हैं तो मां-बाप भी उसी तनाव और अनिश्चितता का शिकार हो जाते हैं। शिक्षा अब सार्वजनिक सेवा नहीं रही बल्कि पैसे बनाने का सिस्टम बन गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि जंतर मंतर परन 'हिन्दू-मुस्लिम' का कोई मामला था, न कोई जाति मतभेद का। सब साझे मकसद के लिए वहां इकट्ठे थे। शिकायत की गई कि वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देने की जगह बहुत हिन्दू-मुस्लिम किया जा रहा है। मीडिया के एक वर्ग की भूमिका वास्तव में राष्ट्र विरोधी है। निष्पक्ष पत्रकारिता करने की जगह वह समाज को साम्प्रदायिक तौर पर बांटने का घिनौना काम कर रहे हैं। अच्छी बात है कि युवाओं ने उन्हें भी शीशा दिखा दिया। भारत में 15-29 साल के 40 करोड़ युवा हैं। वह देख रहे हैं कि सारा ढांचा भ्रष्ट हो चुका है। चुनाव होते हैं। लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं, पर बदलता कुछ नहीं। यह हताशा अब खुली प्रकट होने लगी है। विशेष तौर पर शिक्षा व्यवस्था ढह चुकी है। प्राइवेट और संदिग्ध संस्थाएं परीक्षा सुपरवाइज़ कर रही हैं। अब बताया जा रहा है कि पेपर लीक होने से बचाने के लिए एयर फोर्स के द्वारा इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। क्या नाकामी की इससे बड़ी स्वीकृति हो सकती है कि परीक्षा पेपर एयर फोर्स उठा रही है? नागरिक प्रशासन कहां गया? और पेपर लीक तो ट्रांसपोर्ट से पहले हो रहे हैं। क्या एयरफ़ोर्स को बीच में लाकर जो वास्तव में अपराधी है उनसे ध्यान हटाने का प्रयास हो रहा है ? हकीकत है कि शिक्षा हमारी प्राथमिकता में नहीं है। चीन के उत्थान में उच्च शिक्षा का बड़ा हाथ है। अमेरिका ने भी जो इतनी तरक्की की है वह हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और एमआईटी जैसी उच्च शिक्षा संस्थानों के बल पर की है। हमारा सारा ध्यान 'अपना आदमी' उच्च संस्थानों में बैठाने पर लगा रहता है। योग्यता ज्यादा महत्व नहीं रखती। हमारी शिक्षा व्यवस्था की शोचनीय हालत पर शिक्षाविद् प्रताप भानु मेहता का कटाक्ष है, केन्द्र और प्रदेशों में हमारे शिक्षा मंत्री चीन और दूसरे प्रतिस्पर्धियों को हमारा सबसे बड़ा उपहार है। यह अच्छी बात है कि शिक्षा और उसकी व्यवस्था पर चर्चा तो हो रही है। यह इस कॉकरोच आंदोलन का सबसे बड़ा योगदान होगा। भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन का कहना है कि भारत का युवक विदेशी भूमि पर बैठे कुछ लोगों के हाथ की कठपुतली नहीं है। यह 'विदेशी भूमि' कहां से आ गई? यह तो शुद्ध देसी आन्दोलन है। युवाओं ने भी किसी राजनीतिक दल के पक्ष में या विरोध में नारे नहीं लगाए। वास्तव में कोई भी राजनीतिक दल इस आंदोलन से खुश नहीं है। भाजपा तो वैसे ही इन्हें पसंद नहीं करती। कांग्रेस को चिन्ता है कि कहीं यह आप-2 तो नहीं, आखिर अभिजीत दिपके आप के साथ रह चुके हैं। इसीलिए इस नई पैदाइश के प्रति कांग्रेस का रवैया ठंडा है। आप को चिन्ता है कि कहीं यह उनका युवा समर्थन छीन न ले। जैसे आप शुरू हुई और कॉकरोच जनता पार्टी का उत्थान समानांतर लगता है। द टेलिग्राफ ने इस आंदोलन को बढ़ती बेरोज़गारी, परीक्षा घोटाला और राजनीतिक व्यवस्था से असंतोष का प्रतीक बताया है, पर साथ ही यह भी कहा है कि यह 'विपक्ष की कमी के खालीपन को भी भर रहा है। सीबीएसई में घपले और मिलीभगत का भांडाफोड़ एक 18 वर्ष के साहसी लड़के ने किया है। झारखंड के सार्थक सिद्धांत ने वह कर दिखाया जो बड़े-बड़े नहीं कर सके। पूरी स्पष्टता के साथ उसने अपने ब्लॉग में लिखा है कि, मेरा कहना है कि नियम, शर्तें और धाराएं बदली गई। ऐसा एक विशेष कम्पनी 'कोएम्प' को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया। यह बच्चा न केवल सीबीएसई बल्कि सारे प्रशासन तंत्र पर सवाल खड़े कर रहा है। सार्थक सिद्धांत जैसे प्रतिभाशाली युवा देश का भविष्य हैं। उसे या 15 वर्ष के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी जैसों को देखकर उत्साह होता है कि अभी आशा है, सब कुछ तमाम नहीं हो चुका। सार्थक झारखंड से है तो वैभव बिहार से। दोनों ही पिछड़े प्रदेश माने जाते हैं, पर कितना खज़ाना है इनमें? जिसे जेन-जी कहा जाता है, में कितनी प्रतिभा है? वैभव सूर्यवंशी को तो बीसीसीआई ने अच्छी तरह से सम्भाल लिया है, पर सार्थक जैसे जो लाखों-करोड़ों युवा हैं उनका क्या होगा? यह चिन्ता है। क्या यह भ्रष्ट और असंवेदनशील व्यवस्था इन्हें सम्भाल सकेगी? क्या व्यवस्था इनकी बात सुनेगी या हिन्दू- मुसलमान ही करती जाएगी? दिलचस्प है कि जब सार्थक से उसका फ़ेवरिट कवि पूछा गया तो उसने साहिर लुधियानवी का नाम लिया और जब यह पूछा गया कि साहिर की सबसे पसंद पंक्तियां कौन सी हैं तो उसने बताया, तू हिन्दू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा ! आजकल के 'धुरंधर' युग में यह नौजवान ताज़ा हवा का झोंका नज़र आता है।

कॉकरोच आंदोलन आगे चलता है या फीका पड़ जाता है यह तो समय बताएगा, पर यह लोग जो संदेश दे रहे हैं उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। न केवल पेपर लीक बल्कि बेरोज़गारी उन्हें परेशान कर रही है। क्या कारण है कि कुछ दिनों में ही कॉकरोच जनता पार्टी के फ़ॉलोवर्स 2.2 करोड़ से अधिक हो गए? सरकार को इस हताशा को समझना चाहिए और इस युवा अत्यंत प्रतिभाशाली पीढ़ी के साथ संवाद शुरू करना चाहिए। इनमें राजनीतिक और सरकारी तंत्र के प्रति हताशा क्यों बढ़ रही है? इसका इलाज तत्काल तो नहीं निकाला जा सकता, पर बात तो होनी चाहिए। जंतर मंतर पर उस दिन उपस्थित एक युवा ने पंजाब के क्रान्तिकारी कवि पाश जिसे 1988 में जालंधर में उग्रवादियों ने गोली मार दी थी, की एक कविता की यह पंक्तियां दोहराईं,

सांसद और विधायक भाग रहे, क्या ममता बनर्जी भी टीएमसी छोड़ कर कांग्रेस में जा रही हैं?

पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय अपने सबसे उथल पुथल भरे दौर से गुजर रही है। कभी बंगाल की निर्विवाद ताकत मानी जाने वाली ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस अब अंदरूनी बगावत, सांसदों और विधायकों के पलायन तथा राजनीतिक अस्तित्व के संकट से जूझती दिखाई दे रही है। दिल्ली में सोनिया गांधी के साथ ममता बनर्जी और राहुल गांधी के साथ अभिषेक बनर्जी की बैठकों ने इस संकट को और अधिक राजनीतिक रंग दे दिया है। भले ही कांग्रेस और तृणमूल दोनों सार्वजनिक रूप से किसी विलय की संभावना से इंकार कर रहे हों, लेकिन घटनाक्रम यह संकेत दे रहा है कि बंगाल की राजनीति में एक बड़ा पुनर्संयोजन शुरू हो चुका है। एक तरह से यह साफ नजर आ रहा है कि सिर्फ टीएमसी के सांसद, विधायक और पार्षद ही पाला नहीं बदल रहे हैं खुद टीएमसी प्रमुख अपनी पार्टी को खत्म कर कांग्रेस में वापस लौटना चाह रही हैं। हम आपको बता दें कि दिल्ली में राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की डेढ़ घंटे लंबी मुलाकात तथा उससे पहले सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की बैठक ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। तृणमूल कांग्रेस ने इन बैठकों को लोकतंत्र और संविधान बचाने की साझा प्रतिबद्धता बताया, लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह महज औपचारिक बातचीत नहीं थी। बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद जिस तरह तृणमूल कांग्रेस कमजोर हुई है और पार्टी के भीतर टूट की स्थिति बनी है, उसके बाद कांग्रेस से नजदीकी बनाना ममता बनर्जी की राजनीतिक मजबूरी बन गई है। स्थिति यह है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर विद्रोह अब खुली चुनौती का रूप ले चुका है। पार्टी के 80 में से 58 विधायक अलग होकर निष्कासित विधायक रितब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट के साथ चले गए हैं। इस गुट को विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में मान्यता भी मिल चुकी है। रितब्रत बनर्जी लगातार दावा कर रहे हैं कि वही असली तृणमूल कांग्रेस हैं और कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार के विलय या समझौते के खिलाफ हैं। उनका दावा है कि उनके साथ विधायकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और कई सांसद भी उनके संपर्क में हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस के साथ संभावित विलय या अत्यधिक नजदीकी की अटकलों ने तृणमूल कांग्रेस के भीतर असुरक्षा और बेचैनी को और बढ़ा दिया है। पार्टी के कई विधायक, सांसद और क्षेत्रीय नेता अपनी पूरी राजनीतिक पहचान कांग्रेस विरोध की जमीन पर बनाकर आगे बढ़े थे। ऐसे में उन्हें यह डर सता रहा है कि यदि ममता बनर्जी अंततः कांग्रेस के साथ विलय या व्यापक राजनीतिक समझौते की राह पर चलती हैं, तो उनकी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान समाप्त हो जाएगी। यही कारण है कि तृणमूल में भगदड़ और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। पार्टी के भीतर एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो कांग्रेस में लौटने के पक्ष में नहीं है और वह या तो अलग गुट के साथ रहना चाहता है या फिर नए राजनीतिक विकल्प तलाश रहा है। यही बेचैनी अब खुले विद्रोह और लगातार इस्तीफों के रूप में सामने आती दिखाई दे रही है। संकट केवल विधानसभा तक सीमित नहीं है। संसद में भी तृणमूल कांग्रेस की नींव हिलती दिख रही है। राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे ने पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। उससे पहले सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर राय भी पार्टी और राज्यसभा से इस्तीफा दे चुके हैं। सुष्मिता देव की असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा से मुलाकात ने यह अटकलें और तेज कर दी हैं कि तृणमूल कांग्रेस के कई नेता अब भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख कर सकते हैं। लोकसभा में भी तृणमूल के भीतर विद्रोही खेमे की ताकत बढ़ती दिखाई दे रही है। काकोली घोष दस्तिदार के नेतृत्व वाला गुट दावा कर रहा है कि उसे बीस से अधिक सांसदों का समर्थन हासिल है। सयोनी घोष, माला राय, युसुफ पठान, शताब्दी राय, शत्रुघ्न सिन्हा और रचना बनर्जी जैसे कई चर्चित नाम विद्रोही खेमे के साथ बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह गुट राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार को समर्थन देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिख चुका है। इन घटनाओं के बीच कांग्रेस की भूमिका बेहद दिलचस्प हो गई है। बंगाल कांग्रेस के भीतर भी मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। अधीर रंजन चौधरी और अब्दुल मन्नान जैसे वरिष्ठ नेता ममता बनर्जी के साथ किसी भी तरह की नजदीकी के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। मन्नान ने तो यहां तक कह दिया कि गंदे पानी को साफ पानी में मिलाने से साफ पानी भी गंदा हो जाता है। अधीर रंजन चौधरी ने ममता पर कांग्रेस को बंगाल से खत्म करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब वही ममता गांधी परिवार के सहारे की तलाश में हैं। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने अपेक्षाकृत नरम रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी को भविष्य का प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता मानता है, उसका स्वागत है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए कांग्रेस की छतरी का इस्तेमाल करने वालों के लिए दरवाजे खुले नहीं हैं। यह बयान सीधे तौर पर तृणमूल के उन नेताओं की ओर इशारा माना जा रहा है जिन पर विभिन्न घोटालों के आरोप लगे हैं। हम आपको याद दिला दें कि ममता बनर्जी का पूरा राजनीतिक उदय ही कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह की जमीन पर खड़ा हुआ था। वर्ष 1998 में उन्होंने जोरशोर से कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था। उस समय ममता ने कांग्रेस नेतृत्व पर बंगाल की राजनीति की अनदेखी करने और वामपंथ के सामने आत्मसमर्पण करने का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने खुद को कांग्रेस के विकल्प के रूप में स्थापित किया और धीरे धीरे बंगाल में कांग्रेस की जड़ें कमजोर कर दीं। वर्ष 2011 में वाम मोर्चे को सत्ता से हटाने के बाद ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक विस्तार के लिए कांग्रेस से पूरी दूरी बना ली थी और लगातार गांधी परिवार तथा कांग्रेस नेतृत्व पर तीखे हमले करती रहीं। लेकिन अब जब तृणमूल कांग्रेस भीतर से टूट रही है, सांसद और विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं और राजनीतिक जमीन खिसकती दिखाई दे रही है, तब वही ममता बनर्जी एक बार फिर कांग्रेस की जड़ों की ओर लौटती नजर आ रही हैं। यही वजह है कि दिल्ली में गांधी परिवार के साथ उनकी बैठकों को केवल शिष्टाचार मुलाकात मानने को राजनीतिक विश्लेषक तैयार नहीं हैं। दरअसल, बंगाल की राजनीति अब केवल सत्ता की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि यह अस्तित्व की जंग बन चुकी है। तृणमूल कांग्रेस संगठनात्मक बिखराव से जूझ रही है और बात सिर्फ संसद या विधानसभा में उसके सदस्यों तक सीमित नहीं रह गयी है। बंगाल में कई निगमों से उसके महापौर या पार्षद इस्तीफा दे चुके हैं और पंचायतों में भी इसी तरह के इस्तीफों का दौर जारी है। इस सबके बीच भाजपा यह स्पष्ट कर चुकी है कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के लिए उसके दरवाजे बंद हैं वहीं कांग्रेस इस संकट को अपने पुनर्जीवन के अवसर के रूप में देख रही है।

राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी एकता की राजनीति को मजबूती देने के लिए कांग्रेस बंगाल में नई संभावनाएं तलाश रही है। बहरहाल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ राजनीतिक समझौते की राह पर चलेंगी, या फिर पार्टी के भीतर का विद्रोह उन्हें और कमजोर कर देगा। यदि तृणमूल कांग्रेस का टूटना जारी रहा तो बंगाल की राजनीति में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। आने वाले नगर निकाय चुनाव और उपचुनाव इस बदलाव की पहली बड़ी परीक्षा साबित होंगे। फिलहाल इतना तय है कि बंगाल की राजनीति में शुरू हुई यह हलचल केवल राज्य तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि राष्ट्रीय विपक्ष की राजनीति पर भी इसका गहरा असर पड़ने वाला है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार घाटी ने कदम ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैथलाफा एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार घाटी, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/...)

बाढ़ से निपटने को लेकर तीन तहसीलों में मॉक ड्रिल, परखी गई आपदा प्रबंधन की तैयारियां

बरहज, रुद्रपुर और सलेमपुर में हुआ खोज व बचाव अभियान का जीवंत प्रदर्शन मलबे से घायलों को निकालने, डूबते लोगों को बचाने और प्राथमिक उपचार का हुआ अभ्यास

देवरिया।

आगामी मानसूनी सीजन और संभावित बाढ़ की विभीषिका से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी प्रशासनिक और तकनीकी मुस्तैदी का विधिक परीक्षण शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में गुरुवार को जनपद की तीन अतिसंवेदनशील तहसीलों बरहज, रुद्रपुर और सलेमपुर में बाढ़ नियंत्रण तथा आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए एक वृहद राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। इस दौरान इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम (आईआरएस) के तहत गठित विभिन्न तकनीकी टीमों ने आपातकालीन परिस्थितियों में राहत और बचाव कार्यों का सजीव प्रदर्शन किया। तहसीलवार आयोजित इस सुरक्षा अभ्यास के अंतर्गत बरहज के ग्राम गौरा में उपजिलाधिकारी हरिशंकर लाल के नेतृत्व में नदी में डूब रहे व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए खोज एवं बचाव दल का जीवंत अभ्यास कराया गया। इसी क्रम में तहसील सलेमपुर स्थित आर.एल. एकेडमी विद्यालय में उपजिलाधिकारी दिशा श्रीवास्तव के नेतृत्व में बाढ़ के कारण भवन ध्वस्त होने की विभीषिका पर आधारित मॉक ड्रिल हुई, जिसमें मुख्य अग्निशमन अधिकारी अरुण कुमार की टीम ने मलबे में फंसे घायलों को सुरक्षित निकाला, प्राथमिक उपचार दिया और राहत सामग्री वितरित की। उधर, तहसील रुद्रपुर के ग्राम पिड़रा में उपजिलाधिकारी अवधेश कुमार निगम के नेतृत्व में पीएसी की जल पुलिस ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। प्राकृतिक आपदा के समय विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (डीईओसी) को सक्रिय रखा गया था। कलेक्ट्रेट स्थित इस मुख्य कंट्रोल रूम में इंसिडेंट कमांडर के रूप में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) रामशंकर ने कमान संभाली, जहां उनके साथ अपर पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह, स्वास्थ्य विभाग के डॉ. विपिन रंजन और सिंचाई बाढ़ खंड के सहायक अभियंता अरविंद कुमार पल-पल की विधिक रिपोर्टिंग लेते रहे। आपदा विशेषज्ञ पंकज कुमार के संयोजन में आयोजित इस सफल अभ्यास में पीएसी, अग्निशमन, स्वास्थ्य, वायरलेस और राजस्व विभाग के कर्मियों ने अपनी पेशेवर दक्षता का परिचय दिया।

बालगृह में जिला जज, डीएम और एसपी का निरीक्षण, बच्चों से संवाद कर जाना हाल

बच्चों से सीधे बातचीत कर परखीं आवास, भोजन और पठन-पाठन की व्यवस्थाएं बालगृह अधीक्षक को दो टूक— कोई भी समस्या हो तो सीधे लाएं जिला प्रशासन के संज्ञान में

देवरिया।

बालगृह (बालक) में आवासित बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें बेहतर परिवेश प्रदान करने के उद्देश्य से जिले के तीनों शीर्ष अधिकारियों ने अपनी विधिक और प्रशासनिक सक्रियता दिखाई है। जनपद न्यायाधीश धनेन्द्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी तथा पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर ने गुरुवार को संयुक्त रूप से बालगृह का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों के इस उच्चस्तरीय पैनल ने संस्थान में रह रहे बच्चों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं, स्वास्थ्य, सुरक्षा और पठन-पाठन के स्तर का गहनता से भौतिक सत्यापन किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने बच्चों के बीच बैठकर उनसे सीधा संवाद स्थापित किया। उन्होंने बच्चों की दैनिक पढ़ाई-लिखाई के संबंध में जानकारी ली और स्वयं उनकी कॉपियां खोलकर अक्षरों व लिखे गए शब्दों को देखा। बच्चों की शैक्षणिक प्रगति को आंकने के लिए जिलाधिकारी ने उनसे कुछ सवाल-जवाब भी किए। इसके साथ ही अधिकारियों ने बच्चों के आवास कक्षों, बिस्तरों की स्वच्छता और रसोईघर में बन रहे भोजन की गुणवत्ता को खुद परखा। प्रशासन ने संस्थान में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को शासकीय मानकों के अनुरूप बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। निरीक्षण के उपरांत न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों ने बालगृह के अधीक्षक राम कृपाल को कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों के भरण-पोषण, स्वास्थ्य या शिक्षा में किसी भी स्तर पर कोई व्यावहारिक या विधिक अड़चन आती है, तो उसे दबाने के बजाय तत्काल जिला प्रशासन और न्यायिक पीठ के संज्ञान में लाया जाए। शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि बालगृह की आंतरिक व्यवस्था को पूरी तरह सुव्यवस्थित रखना और बच्चों को घरेलू माहौल प्रदान करना प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस महत्वपूर्ण निरीक्षण के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव, एसीजीएम, मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह सहित अन्य न्यायिक व प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी विंग कमांडर आलोक सक्सेना को भावभीनी विदाई

कुशीनगर।

जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में आयोजित विदाई एवं सम्मान समारोह में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी विंग कमांडर आलोक सक्सेना (अप्रा.) को भावभीनी विदाई दी गई। जनपद में अपना कार्यकाल पूर्ण करने के बाद उन्होंने अपना कार्यभार नवागत अधिकारी कर्नल डॉ. सुधाकर त्यागी (अप्रा.) को सौंप दिया। समारोह में उपस्थित पूर्व सैनिकों ने पुष्पमालाएं भेंट कर विंग कमांडर आलोक सक्सेना के कार्यों की सराहना की। अपने संबोधन में उन्होंने पूर्व सैनिकों एवं कार्यालय कर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कुशीनगर में उनका कार्यकाल बेहद सुखद और यादगार रहा।

उन्हें सभी का भरपूर सहयोग, सम्मान और स्नेह प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी पूर्व सैनिकों की आवश्यकता पड़ने पर वे हर संभव सहयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे। कार्यभार ग्रहण करने के बाद कर्नल डॉ. सुधाकर त्यागी ने कहा कि विंग कमांडर आलोक सक्सेना ने

कर्नल डॉ. सुधाकर त्यागी ने संभाला कार्यभार, पूर्व सैनिकों के हित में कार्य करने का दिया भरोसा

प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर पूर्व सैनिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे भी पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के हितों की रक्षा तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। समारोह में वरिष्ठ पूर्व सैनिक मेजर (डॉ.) महेश वरनवाल, कैप्टन लाल बहादुर त्रिपाठी, कैप्टन डी.एस. पाण्डेय, कैप्टन शमशुद्दीन, अनिल सिंह, एस.पी. गुप्ता सहित बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन कार्यालय के प्रभाकर नाथ तिवारी, राजेश कुमार गुप्ता, धर्मशीला, जालंधर एवं अन्य कर्मचारियों के सहयोग से संपन्न हुआ।

विश्व योगासना चैंपियनशिप में देवरिया की गुड़िया देवी ने जीता स्वर्ण

(वेबवार्ता)

मोहल्ला निवासी गुड़िया देवी वर्तमान

भटनी देवरिया। देवरिया जिले की बेटी एवं शहीद राजकुमार गुप्ता की पत्नी गुड़िया देवी ने अहमदाबाद (गुजरात) में आयोजित प्रथम वर्ल्ड योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 में सीनियर-बी वर्ग के ट्रेडिशनल योगासना (इंडिविजुअल इवेंट) में स्वर्ण पदक जीतकर देश और जिले का नाम रोशन किया। नगर पंचायत भटनी के हरिकीर्तन में बीएसएफ जवान के रूप में देश की सेवा कर रही हैं। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। गुड़िया देवी ने अपनी सफलता का श्रेय बीएसएफ योगासना टीम के चीफ कोच इंस्पेक्टर सुभाष बिश्नोई, परिवारजनों एवं टीम के सहयोग को दिया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी वह एशियन योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं।

भटनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु की हुई प्रार्थना

माँ जलपा देवी मंदिर में पूजन-अर्चन व आरती कार्यक्रम आयोजित

भटनी देवरिया।

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के ऐतिहासिक अवसर पर भटनी मंडल अध्यक्ष रोहित मिश्रा प्यासी के नेतृत्व में भटनी स्थित माँ जलपा देवी मंदिर में विधिवत पूजन-अर्चन एवं आरती कर उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं निरंतर राष्ट्रसेवा हेतु प्रार्थना की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रामपुर कारखाना विधायक सुरेंद्र चौरसिया उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का दूरदर्शी नेतृत्व, सेवा, सुशासन और राष्ट्रहित के प्रति समर्पण सभी के लिए प्रेरणास्रोत है तथा उनके नेतृत्व में भारत विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक गौरव की नई ऊँचाइयों को प्राप्त कर रहा है। विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर पंचायत अध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता उपस्थित रहे।

इस अवसर पर मंडल महामंत्री कृष्ण दत्त मिश्रा, मंडल महामंत्री आशीष पासवान, मंडल उपाध्यक्ष अभय तिवारी, मंडल उपाध्यक्ष विशंभर तिवारी, दीनदयाल जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष हितेंद्र तिवारी, पूर्व मंडल अध्यक्ष योगेश प्रजापति, हिंदू युवा वाहिनी के अजय तिवारी, धीरेंद्र मिश्रा, व्यापार मंडल अध्यक्ष नवीन रौनियार, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष मीडिया प्रभारी, श्रीमती शकुंतला यादव,शेषनाथ कुशवाहा भटनी मंडल,आशा ओझा सहित पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिगण, व्यापारी बंधु एवं क्षेत्र के सम्मानित नागरिक उपस्थित रहेकार्यक्रम का संचालन भटनी मंडल के युवा नेता प्रतीक मिश्रा ने किया।

गैस एजेंसी पर मारपीट का आरोप, पीड़ित ने थाने में दी तहरीर

जांच कर कार्रवाई की मांग, मुकदमा दर्ज नहीं

भटनी देवरिया।

थाना भटनी क्षेत्र के ग्राम सिहपुर टोला गायधार निवासी वृजेश कुमार यादव ने थाना भटनी में तहरीर देकर आरोप लगाया है कि बृहस्पतिवार को गैस सिलेंडर लेने के दौरान गैस रिसाव की शिकायत करने पर एजेंसी परिसर में विवाद हो गया। तहरीर के अनुसार, शिकायत के बाद कुछ लोगों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, जिससे उन्हें चोटें आईं। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के दौरान उनका मोबाइल फोन भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। प्रार्थी ने मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित लोगों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।

खरगे की अध्यक्षता में कांग्रेस सचिवों और राज्य अध्यक्षों की आपात बैठक, राजनीतिक रणनीति पर हुई चर्चा

नई दिल्ली । कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को पार्टी के सभी महासचिवों, प्रभारियों और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा की गई। कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाने की घोषणा की है। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल शामिल हुए। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी, तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष बोम्मा महेशकुमार गौड़, गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश चोडणकर और पंजाब के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग भी बैठक में उपस्थित थे। सभी प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्षों, महासचिवों और राज्य प्रभारियों की एक हफ्तेभर की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, आज महासचिवों, प्रभारियों और PCC अध्यक्षों की मीटिंग में मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा चुनाव नॉमिनेशन के रिजेक्शन के मामले पर विस्तार से चर्चा हुई। हम इस मुद्दे पर राजनीतिक और कानूनी तौर पर लड़ेंगे। कमिटी ने यही तय किया और इसी पर चर्चा की। बहुमत बनाने का यही तरीका है। उन्होंने आगे कहा, बहुमत बनाने का यही तरीका है। वह दूसरी पार्टियों के सभी सांसदों को लेकर ऊपर इस्तीफा दिला रहे हैं और उन्हें भाजपा संसद बना रहे हैं। दूसरी तरफ, यह असल में वोटिंग के बाद, वोट चोरी के बाद, सीट चोरी है। यह साफ तौर पर सीट चोरी है। हम इसके खिलाफ कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। फिर हमारी मीटिंग में देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। मुख्य रूप से आर्थिक संकट के मुद्दे पर। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की कीमतें दिन-ब-दिन बढ़ रही हैं। लोग बहुत परेशान हैं। सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बेरोजगारी चरम पर है। रुपया पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। युवा बहुत चिंतित है। वह अपने भविष्य को लेकर परेशान है। रोजगार नहीं है। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए खरगे ने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दों पर समन्वय बढ़ाने और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का मुकाबला करने के लिए विपक्षी गठबंधन के सहयोगियों के बीच अधिक तालमेल स्थापित करने के लिए इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हर दो महीने में बैठक करेंगी। खरगे ने बताया कि बैठक में 25 पार्टियों ने भाग लिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, यह सहमति बनी कि भारत गठबंधन के सभी दल हर दो महीने में मिलेंगे। अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में होगी। खरगे ने कहा कि इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), वोट की लूट और चुनावी कदाचार के मुद्दे पर भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखने का फैसला किया है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, एसआईआर, वोट की लूट और चुनाव में धांधली के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजने पर सहमति बनी। यह पत्र जल्द ही भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंप दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग पर सर्वसम्मति से सहमति बनी है क्योंकि उन्होंने नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल हुए लाखों युवाओं के साथ हुए विश्वासघात की अध्यक्षता की है।

पुणे में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन

पुणे । कॉकरोच जनता पार्टी ने गुरुवार को पुणे के सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन किया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी शामिल हुए। सैकड़ों छात्र और मगवेंक पोस्टर-बैनर लेकर पहुंचे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। सोनम वांगचुक ने सीजेपी का शिक्षा घोषणापत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि इसमें पेपर लीक रोकने, समय पर रिजल्ट जारी करने, भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने, परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय करने और परीक्षा में देरी-गड़बड़ियों से छात्रों को समस्याओं के समाधान पर जोर दिया गया है। सीजेपी फाउंडर दीपके ने अपने भाषण में दावा किया कि दिल्ली में जंतर-मंतर से ज्यादा लोग पुणे में जुटे हैं। दीपके ने सरकार के सामने 5 मांगे भी रखीं। इसके अलावा एनसीआरटी की किताबों में मराठा साम्राज्य का मैप दोबारा शामिल करने की मांग की। दरअसल,एनसीआरटी ने 2025-26 सत्र के लिए कक्षा 8 की किताब में मराठा साम्राज्य का एक मैप पब्लिश किया था। इसमें राजस्थान के कुछ हिस्सों को मराठा क्षेत्र दिखाया गया। कुछ इतिहासकारों और पूर्व शाही परिवारों ने इसपर आपत्ति जताई, जिसके बाद एनसीआरटी ने मार्च 2026 में मैप हटा दिया। दीपके ने 11 जून से देशभर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसकी शुरुआत पुणे से हुई है। सीजेपी ने एक्स पर बताया कि 12 जून को लखनऊ में अगला प्रदर्शन होगा। दीपके जयपुर, अमृतसर और बेंगलुरु समेत कई शहरों में जाएंगे। इसके बाद 20 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचेंगे। 6 जून को पार्टी ने जंतर-मंतर पर अपना पहला प्रदर्शन किया था। 5 घंटे चले प्रदर्शन में हजारों लोग जुटे थे। पुणे में प्रदर्शन से पहले दीपके ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी वायरल तस्वीर को एआई जनरेटेड बताया। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री से कैसे मिल सकता हूं? मैं अमेरिका में सिर्फ एक स्टूडेंट था। सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री से मिलने की प्रक्रिया कितनी सख्त होती है।

'फाउंडर अभिजीत बोले- एनसीआरटी में मराठा साम्राज्य का मैप दोबारा जोड़ा जाए, वांगचुक ने शिक्षा घोषणापत्र जारी किया

हस्ताक्षर जालसाजी मामले में अभिषेक बनर्जी से हुई छह घंटे पूछताछ, देर रात सीआईडी ऑफिस से निकले

कोलकाता । तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के चयन को लेकर कथित हस्ताक्षर जालसाजी मामले में सीआईडी ने गुरुवार को लगभग छह घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद वह देर रात सीआईडी मुख्यालय से रवाना हुए। कलकत्ता उच्च न्यायालय से किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक मिलने के बाद अभिषेक बनर्जी शाम करीब 5:50 बजे सीआईडी मुख्यालय पहुंचे और रात लगभग 11:30 बजे वहां से निकले। मुख्यालय से बाहर निकलते समय अभिषेक बनर्जी ने मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। अभिषेक बनर्जी इससे पहले सीआईडी के तीन समन को नजरअंदाज कर चुके थे। उन्होंने बीमारी और उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका का हवाला देते हुए पेशी से छूट मांगी थी। बंगाल की सत्ता में बदलाव के बाद किसी राज्य जांच एजेंसी के सामने यह अभिषेक बनर्जी की पहली पेशी थी। इससे पहले उनसे कोयला तस्करी और स्कूल भर्ती घोटाले के मामलों में ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां कई बार पूछताछ कर चुकी हैं। अभिषेक बनर्जी दिल्ली से गुरुवार शाम करीब 4:30 बजे कोलकाता लौटे। वह पिछले तीन दिनों से दिल्ली में थे, जहां उन्होंने राहुल गांधी समेत विपक्षी गठबंधन के नेताओं के साथ कई बैठकें की। कोलकाता हवाई अड्डे पर उनके पहुंचने के दौरान अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला। वहां मौजूद लोगों के एक समूह ने उनके खिलाफ सिम्पेथर चोर के नारे लगाए। इसके बाद अभिषेक बनर्जी अपने कालीघाट स्थित आवास पर करीब 30 मिनट रुके और फिर अदालत द्वारा निर्धारित समय-सीमा से लगभग 10 मिनट पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भवानी भवन स्थित सीआईडी मुख्यालय पहुंचे।

केरलम में निपाह वायरस लौटा

तिरुवनंतपुरम । केरलम में इस साल निपाह वायरस का पहला केस मिला है। इसकी जानकारी गुरुवार को सामने आई। मरीज 43 साल का है और कोझिकोड का रहने वाला है। राज्य सरकार ने रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। मरीज को हल्का बुखार आने पर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। बाद में कोझिकोड मेडिकल कॉलेज भेजा गया। उसकी हालत गंभीर है और वह वेंटिलेटर पर है। स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने कहा, मरीज कई लोगों के संपर्क में आया था। अस्पताल के स्टाफ और उसके संपर्क में आए संभावित लोगों को क्वारंटीन रहने को कहा गया है। फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। 2018 के बाद से केरलम में छठी बार संक्रमण फैला है। आखिरी बार दो साल पहले 2024 में दो केस मिले थे। इनमें एक मरीज की जान चली गई थी। अधिकारियों के मुताबिक, मरीज ने हाल ही में एक गोदाम किराए पर लिया था और खुद उसकी सफाई की थी। आशंका है कि इसी दौरान वह संक्रमण की चपेट में आया। निपाह वायरस मुख्य रूप से फ्रूट बैट (फल खाने वाले चमगादड़ों) से फैलता है।

मालवीय नगर अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई, फर्जी रिपोर्ट पर लाइसेंस देने वाला हेल्थ इंस्पेक्टर बर्खास्त

दिल्ली । मालवीय नगर इलाके में हुई हालिया आग की घटना के बाद दिल्ली नगर निगम ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। निगम के जन स्वास्थ्य विभाग ने कर्तव्य में घोर लापरवाही, ढिलाई और भ्रष्टाचार के आरोप में साउथ जोन में तैनात सहायक जन स्वास्थ्य निरीक्षक प्रिंस मल को अनुचित सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। साथ ही, साउथ जोन उप स्वास्थ्य अधिकारी संजय सिंह का तबादला कर दिया गया है। विभागीय आदेश के अनुसार, मालवीय नगर के ब्लॉक सी (269, सी-2) स्थित एक परिसर में बिना बैठने की व्यवस्था वाले चाय और स्नैक्स के व्यापार लाइसेंस का आवेदन आया था। उस इंस्पेक्टर को 17 मार्च 2026 को इस परिसर का निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी गई थी। परंतु, उन्होंने बिना किसी वैध कारण के इस पहल को 78 दिनों तक दबाए रखा। इसके बाद 2 जून 2026 को उन्होंने एक अत्यंत सतही और संदिग्ध जमीनी निरीक्षण किया। उन्होंने जानबूझकर कागजों में दर्ज विवरण और जमीन की वास्तविक स्थिति को छुपाया और फर्जी तरीके से लाइसेंस देने की सिफारिश कर दी, जिसके बाद उसी दिन लाइसेंस जारी भी हो गया। हैरान करने वाली बात यह रही कि इस भ्रामक रिपोर्ट के आधार पर 2 जून को लाइसेंस जारी हुआ और ठीक उसके अगले दिन, यानी 3 जून 2026 को उसी संबंधित परिसर में भीषण आग लग गई। इस हादसे ने निगम प्रशासन और सुरक्षा मानकों की पोल खोल कर रख दी। निगम द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि कर्मचारी का यह आचरण न केवल उनके काम के प्रति घोर लापरवाही को दर्शाता है, बल्कि उनकी ईमानदारी पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। ऐसे में उन्हें पद पर बनाए रखना जनहित के खिलाफ होगा।

जश्न मनाने का समय है, लेकिन निंदा के लिए नहीं, भारतीय की मौत पर पीएम मोदी पर बरसे ओवैसी

हैदराबाद । एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ओमान तट के पास एक वाणिज्यिक जहाज पर हुए अमेरिकी सैन्य हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जश्न मनाने का समय है, लेकिन भारतीय नागरिकों की मौत पर अमेरिका की निंदा करने का समय नहीं है।

भारतीयों की जान बचाना सरकार की पहली जिम्मेदारी

ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का पहला कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद और चिंताजनक है कि भारतीयों की मौत के बावजूद सरकार की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। उन्होंने लिखा कि भारतीयों की जान बचाना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री के पास उत्सव मनाने का समय है, लेकिन भारतीयों की हत्या पर अमेरिकी सेना की निंदा करने का समय नहीं है।

केंद्र सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप

ओवैसी ने दावा किया कि मोदी सरकार बार-बार अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में काम करने वाले भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रूस अब भी भारतीय युवाओं की भर्ती सैनिकों के रूप में कर रहा है और उनकी मौत की खबरें सामने आती हैं, लेकिन सरकार प्रभावी कदम उठाने में असहाय नजर आती है। इसके अलावा उन्होंने चीन और गलवान घाटी के मुद्दे का भी उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार की विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति पर सवाल उठाए।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, भारत सरकार ने गुरुवार को पुष्टि की कि पिछले चार दिनों के दौरान ओमान तट के पास अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में भारतीय चालक दल सदस्यों वाले तीन व्यापारी जहाज प्रभावित हुए। इनमें से एक हमले में तीन भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। भारत ने इस घटना पर अमेरिका के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है और नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस मुद्दे को अमेरिकी प्रशासन के समक्ष मजबूती से उठाया गया है। भारत ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव को लेकर भी चिंता व्यक्त की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, भारत ने इस घटना को लेकर अमेरिकी राजनयिक को तलब कर अपना विरोध दर्ज कराया है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन सुनिश्चित करने की मांग भी की गई है।

ममता और टीएमसी के साथ खड़ा रहना मेरा फर्ज- शत्रुघ्न सिन्हा

कोलकाता । तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में फूट की चर्चाओं के बीच पार्टी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि वह ममता बनर्जी और टीएमसी के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए सिन्हा ने कहा कि ममता बनर्जी और पार्टी का साथ देना उनका कर्तव्य है। शत्रुघ्न सिन्हा ने सबसे पहले आसनसोल और पश्चिम बंगाल की जनता का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वहां के लोगों ने उन्हें बहुत प्यार और समर्थन दिया है। उन्होंने बताया कि वह ममता बनर्जी के बुलावे और उनके निर्देश पर ही आसनसोल आए थे। उन्होंने वहां पहली बार उपचुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज की थी। इसके बाद दूसरी बार भी वह बड़े अंतर से चुनाव जीते। सिन्हा ने कहा कि वह बंगाल के सभी लोगों के लिए काम करते हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए सिन्हा ने कहा कि 2019 में पटना से चुनाव हारने के बाद वह कठिन समय से गुजर रहे थे। उस वक्त बहुत कम लोग उनके साथ खड़े थे। ममता बनर्जी उन गिने-चुने लोगों में से थीं जिन्होंने उन्हें सहारा दिया। ममता बनर्जी चाहती थीं कि वह बिना किसी ब्रेक के संसद में बने रहें। उन्हीं के कहने पर उन्होंने आसनसोल से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। पिछले कुछ दिनों से सिन्हा को लेकर कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वह बागी गुट में शामिल हो गए हैं।

मोहन भागवत की ट्रेन पर पथराव- शताब्दी एक्सप्रेस के E-1 कोच को बनाया निशाना, आरएसएस प्रमुख सुरक्षित; जांच शुरू

फिरोजाबाद ।

संघ प्रमुख मोहन भागवत शताब्दी एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव क्लास के ई-1 कोच में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन जब मक्खनपुर-फिरोजाबाद के बीच से गुजर रही थी, तभी अचानक बोगी को निशाना बनाकर पत्थर से हमला किया गया। पत्थर सीधे उसी बोगी पर जा लगा जिसमें संघ प्रमुख मौजूद थे, जिससे खिड़की का एक शीशा क्षतिग्रस्त हो गया।

लखनऊ से दिल्ली जा रही डबलडेकर ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस पर गुरुवार शाम मक्खनपुर और फिरोजाबाद रेलवे स्टेशनों के बीच कुछ अज्ञात असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। इस घटना से रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में खलबली मच गई, क्योंकि इसी ट्रेन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत भी सवार थे। गनीमत यह रही कि इस पथराव में संघ प्रमुख पूरी तरह सुरक्षित हैं।

ई-1 कोच में थे मोहन भागवत

संघ प्रमुख मोहन भागवत शताब्दी एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव क्लास के ई-1 कोच में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन जब मक्खनपुर-फिरोजाबाद के बीच से गुजर रही थी, तभी अचानक बोगी को निशाना बनाकर पत्थर से हमला किया गया। पत्थर सीधे उसी बोगी पर जा लगा जिसमें संघ प्रमुख मौजूद थे, जिससे खिड़की का एक शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि, गनीमत यह रही कि मोहन भागवत दूसरी साइड बैठे थे। पत्थर से खिड़की का कांच टूट गया। सुरक्षा और सतर्कता को देखते हुए ट्रेन को बीच रास्ते में कहीं भी रोका नहीं गया और उसे सीधे आगे के लिए रवाना रखा गया। घटना की सूचना मिलते ही टूंडला जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस के आला अधिकारी भारी फोर्स के साथ मुस्तैद हो गए। शाम 7:34 बजे जैसे ही शताब्दी एक्सप्रेस टूंडला जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, सुरक्षा घेरा बेहद सख्त कर दिया गया।

एजेंसियों ने ली राहत की सांस

सुरक्षा के कड़े प्रोटोकॉल और स्टेशन पर भीड़भाड़ को देखते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत को ट्रेन की बोगी से नीचे नहीं उतारा गया। सुरक्षाकर्मियों और अधिकारियों ने बोगी के भीतर जाकर उनसे मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना। संघ प्रमुख के पूरी तरह सही-सलामत होने की पुष्टि के बाद ही सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली।

जांच में जुटी टीमें, 7 मिनट बाद दिल्ली रवाना हुई ट्रेन

टूंडला जंक्शन पर सुरक्षा जांच और जरूरी कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, ट्रेन को शाम 7:41 बजे दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया। इस बेहद संवेदनशील मामले को गंभीरता से लेते हुए आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीमों ने मक्खनपुर-फिरोजाबाद रेल खंड के आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया।

आरपीएफ का बयान

पटरी के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और स्थानीय इनपुट के आधार पर पथराव करने वाले अराजक तत्वों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। - विनीत सागर, सहायक सुरक्षा आयुक्त, आरपीएफ।

टीएमसी का खेल खत्म, 1-2 दिन में साफ होगा भविष्य- निशिकांत दुबे

नई दिल्ली। बीजेपी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने 11 जून को दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस जल्द ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल के बीच अगले कुछ दिनों में हालात और साफ हो जाएंगे। झारखंड के देवघर में बात करते हुए, दुबे ने ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पार्टी के भविष्य के बारे में अपनी पिछली बातों का जिक्र किया और तेजी से हो रहे राजनीतिक बदलावों की ओर इशारा करते हुए कहा कि बाबा की नगरी में कही गई हर बात सच साबित होती है। 1-2 दिनों में हमें और जानकारी मिल जाएगी। उनके ये बयान झारखंड के अंदर चल रही आपसी कलह के बीच आए हैं, जहां कई इस्तीफे हुए हैं, गुटबाजी के आरोप लगे हैं।

महाराष्ट्र में सियासी भूकंप! उद्धव ठाकरे के 7 एमपी शिंदे गुट के संपर्क में

मुंबई। महाराष्ट्र में संभावित राजनीतिक दलाव को लेकर नई अटकलें शुरू हो गई हैं। खबरों के मुताबिक, उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना के सात सांसद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे के संपर्क में हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, 7 जून को एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे के दौरान एक बैठक हुई थी और बताया जा रहा है कि इस बातचीत में ठाकरे खेमे के कई सांसद मौजूद थे। हालांकि अभी पूरी जानकारी साफ नहीं है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में शिवसेना के कुछ सांसदों के राजनीतिक भविष्य और उनके शिंदे गुट में शामिल होने की संभावना पर चर्चा हुई। इसके अलावा, खबरों के अनुसार शिंदे गुट के नेताओं ने दिल्ली में हुई बातचीत के दौरान एक राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया। केंद्रीय कैबिनेट के संभावित विस्तार को लेकर चल रही अटकलों के बीच, ऐसी खबरें हैं कि केंद में प्रतिनिधित्व को लेकर आश्वासन दिया गया हो सकता है। कहा जा रहा है कि ठाकरे खेमे के एक सांसद को केंद्रीय कैबिनेट में जगह देने का वादा किया गया था, जबकि अन्य सांसदों को महत्वपूर्ण संगठनात्मक और राजनीतिक जिम्मेदारियां सौंपने का भरोसा दिया गया था। हालांकि, इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित किसी भी नेता ने सार्वजनिक रूप से इन्हें स्वीकार नहीं किया है। सूत्रों के अनुसार, एकनाथ शिंदे और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे कई महीनों से ठाकरे गुट के नेताओं के संपर्क में हैं। कहा जा रहा है कि पिछले छह महीनों में दिल्ली में कई बार अलग-अलग और ग्रुप लेवल पर बैठकें हुई हैं। ऐसी भी चर्चा है कि शिंदे गुट के केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव के दिल्ली स्थित आवास पर शिवसेना के कुछ सांसदों के साथ बातचीत हुई थी। इन बैठकों के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इस चर्चा ने शिंदे के नेतृत्व में 2022 में हुए उस विद्रोह की यादें ताजा कर दी हैं, जिसने शिवसेना को दो हिस्सों में बांट दिया था और राज्य की राजनीतिक तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया था। हालांकि किसी भी गुट की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में पर्दे के पीछे बातचीत और संभावित दल-बदल की खबरों की चर्चा जोरों पर है। सूत्रों के अनुसार, मुंबई के दो सांसदों को छोड़कर बाकी सात सांसदों के शिंदे गुट के संपर्क में होने की बात कही जा रही है। यह भी दावा किया जा रहा है कि इन सांसदों ने दिल्ली दौरे के दौरान शिंदे से मुलाकात की थी। हालांकि, किसी भी सांसद ने इन खबरों की सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं की है।

'खबरों के मुताबिक, उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना के सात सांसद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे के संपर्क में हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, 7 जून को एकनाथ शिंदे के दिल्ली दौरे के दौरान एक बैठक हुई थी और बताया जा रहा है कि इस बातचीत में ठाकरे खेमे के कई सांसद मौजूद थे।

पाकिस्तानी सेना ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर बरसाई गोलियां, पीओके में 16 लोगों की मौत

लाहौर । पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके के राजकोट में एक और दुखद और खूनी घटना सामने आई है. पाकिस्तानी सेना के जवानों और रेंजर्स ने शहर के ईदगाह मैदान में जमा हजारों निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दीं. आम नागरिकों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक खौफनाक मंजर में बदल गया. ये लोग सस्ता आटा, चावल, बिजली और बुनियादी अधिकारों की मांग कर रहे थे. राकलकोट में 60,000 से 70,000 लोग जमा हुए थे, तभी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोलियां बरसा दीं. प्रदर्शनकारियों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे.